

राजस्थान राज्य  
बनाम  
मूलचन्द और अन्य  
14 अक्टूबर, 2004  
[ न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर ]

राजस्थान कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961; धारा 17 और 28 / राजस्थान कृषि उपज बाजार नियम, 1983: एक लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट द्वारा कृषि उपज पर बाजार शुल्क के भुगतान की चोरी के खिलाफ शिकायत-निचली अदालत ने लाइसेंसधारक को दोषी पाया, उसे तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और उसे शुल्क की चोरी की राशि जमा करने का निर्देश दिया-अपीलीय अदालत ने सजा को कम करते हुए पुष्टि की यू. पी. अधिनियम से संबंधित निर्णय के आधार पर जमा किए गए शुल्क की वापसी का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई दोषसिद्धि-अपील पर आयोजित: उत्तर प्रदेश अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और राजस्थान अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले मामले की सेवा में दबाव नहीं डाला जा सकता है-उच्च न्यायालय दोनों अधिनियमों की भाषा में अंतर को नोटिस करने में विफल रहा-न ही उसने राजस्थान के मामलों में उत्तर प्रदेश मामले में निर्णय को लागू करने का कोई कारण दिया-इसलिए, मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964-धारा 17।

कृषि उत्पादन मंडी समिति, जोधपुर में उत्तरदाताओं में से एक-लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के रिकॉर्ड के निरीक्षण पर यह पाया गया संबंधित अधिकारियों द्वारा कि प्रत्यर्थी राजस्थान कृषि बाजार नियमों के तहत निर्धारित घोषणा पत्र का उपयोग नहीं कर रहा था और उसके द्वारा शुल्क की कुछ राशि की चोरी देखी गई थी। कर्तव्य की वसूली के लिए अधिकारियों द्वारा उपयुक्त न्यायालय के समक्ष एक शिकायत दायर की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों को बाजार शुल्क/शुल्क की चोरी के कथित अपराध का दोषी पाया और उन्हें तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और शुल्क की चोरी की राशि जमा करने का आदेश दिया। सजा को कम करते हुए अपीलीय अदालत ने आदेश की पुष्टि की। दूसरी अपील पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को खारिज कर दिया और अधिकारियों को यह मानते हुए शुल्क की बरामद राशि को वापस करने का निर्देश दिया कि बाजार शुल्क का भुगतान करने का दायित्व खरीदार पर है न कि लाइसेंसधारी पर। अतः वर्तमान अपील और संबंधित अपील।

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था-यह बताएँ कि व्यापारियों का दायित्व और एजेंटों को राजस्थान अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है; कि यू. पी. अधिनियम के तहत प्रावधान अलग हैं और इस तरह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं जो के प्रावधानों के तहत शामिल थे राजस्थान अधिनियम।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

1.1 . राजस्थान कृषि उपज बाजार अधिनियम और यू. पी. कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम के बीच एक बुनियादी अंतर है कि जहाँ तक बाजार शुल्क लगाने का संबंध है, यू. पी. अधिनियम में खरीदार पर दायित्व तय करने का एक विशिष्ट संदर्भ है और राजस्थान अधिनियम देयता लाइसेंसधारी पर है। [ 503 - एफ ]

1.2 . उच्च न्यायालय ने दोनों के बीच प्रासंगिक अंतर पर ध्यान नहीं दिया राजस्थान अधिनियम की धारा 17 बनाम उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 17। कृषि उत्पादन मंडी समिति, हल्द्वानी और अन्य के मामले में तर्क लागू किया गया। जहाँ तक राजस्थान के मामलों का संबंध है, उन्हें सेवा में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कानूनी स्थिति अलग है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रावधानों की तुलना किए बिना कोई कारण नहीं बताया है कि उसने क्यों सोचा कि उत्तर प्रदेश का मामला वर्तमान अपीलों पर लागू था। एकमात्र इस आधार पर कि उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश अधिनियम और राजस्थान अधिनियम की भाषा में अंतर को नोटिस करने में विफल रहा, मामलों को उच्च न्यायालय को प्रेषित करने की आवश्यकता है। इसलिए, मामलों

को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। [ 504 – सी-ई ]

कृषि उत्पादन मंडी समिति, हल्द्वानी और अन्य वी. इंडियन वूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य [ 1996 ] 3 एससीसी 321, असहमत।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं. 667/1999

राजस्थान उच्च न्यायालय के 13.1.98 दिनांकित निर्णय और आदेश से S.B.Crl में 1995 का आर. पी. सं. 387

**अपीलार्थी की ओर से सुश्री मधुरिमा तातिया और इंद्रा मकवाना, माननीय अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए श्री मनीष सिंघवी, सौरभ अजय, पी. वी. योगेश्वरन, आर. के. गुप्ता, के. के. गुप्ता, सुशील के. जैन, ए. पी. धमीजा, एच. डी. थानवी, सारद सिंघानिया, एल. पी. सिंह, पुनीत जैन और श्रीमती प्रतिभा जैन माननीय अधिवक्तागण।**

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने दिया इन दोनों अपीलों में समान मुद्दे शामिल हैं और 2002 की आपराधिक अपील सं. 435 उस निर्णय पर आधारित थी जो है - सी. आर. एल. में चुनौती का विषय। 1999 का ए. सं. 667।

जहाँ तक 1999 के Crl.A. संख्या 667 का संबंध है, पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं -

इस प्रकार है:

प्रत्यर्थी ने व्यापारी और कमीशन के रूप में लाइसेंस संख्या 55 प्राप्त किया था।

कृषि उपज मंडी समिति, जोधपुर से एजेंट 'ए' वर्ग (इसके बाद)

'समिति' के रूप में संदर्भित)। उत्तरदाताओं के 16.12.1989 रिकॉर्ड पर थे

निरीक्षण किया गया। यह पाया गया कि जारी किए गए घोषणा पत्र शर्तों में नहीं थे

राजस्थान कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम')

और राजस्थान कृषि उपज बाजार नियम, 1963 (संक्षेप में

'नियम') क्योंकि उनमें वास्तविक विवरण और चोरी का खुलासा नहीं था

9.1.1990 उत्तरदाताओं पर उपरोक्त राशि जमा करने के लिए, जब पहले नोटिस का कोई जवाब नहीं आया तो 11.4.1990 को एक और नोटिस दिया गया

चूंकि दूसरे नोटिस का भी कोई जवाब नहीं आया था, इसलिए शिकायत वाद संख्या- 115/ 1990 दिनांक 16.6.1990 को समक्ष अदालत के समक्ष अधिनियम की धारा 17 की आवश्यकताओं का पालन न करने का अपराध, जिससे अधिनियम की धारा 28 के तहत कार्रवाई की जा सके किया गया। माननीय अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 जोधपुर में मामले की सुनवाई की और पाया कि प्रतिवादियों को मंडी शुल्क की चोरी के कथित अपराध का दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई उत्तरदाता नं. 1 तीन महीने के लिए साधारण कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना निश्चित अवधि के लिए लगाया गया। प्रत्यर्थियों को Rs.87,639.90 की चोरी की गई राशि अदालत में जमा करने के लिए निर्देश दिया गया।

उत्तरदाताओं ने कथित निर्णय के विरुद्ध विधिक वैधता पर प्रश्न उठाते हुए Crl. Appl. संख्या-46/1995 दायर किया। अपील की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम मामले, जोधपुर द्वारा की गई और उसका निपटारा किया गया। अपील में केवल राजस्थान राज्य को एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था कि समिति को। हालाँकि अपीलीय अदालत को कोई गुण नहीं मिला और उसी को खारिज कर दिया। हालाँकि, सजा थी अदालत के उठने तक कारावास में घटा दिया गया। प्रतिवादियों ने एस. बी. के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 387/1995 दाखिल कर निम्न न्यायालय के अशुद्धता पर प्रश्न उठाया। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया, और आदेश दिया दिनांक 13.1.1998 के निर्णय द्वारा बरामद राशि की वापसी करें। पूरा आधार फैसला कृषि उत्पादन में अदालत के फैसले के इर्द-गिर्द घूमता है। - मंडी समिति, हल्द्वानी और अन्य वी. इंडियन वूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड और एन. आर. [ 1996 ] 3 एस. सी. सी. 321 (1996) 2 सुप्रीम 726। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कथित रूप से इस न्यायालय के

निर्णय के बाद बाजार शुल्क का भुगतान करने का दायित्व खरीदार का था और वर्तमान उत्तरदाताओं का बाजार शुल्क का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था।

संबंधित अपील में उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय था उत्तरदाताओं द्वारा दायर एक याचिका में इसका पालन किया गया।

अपीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य और समिति ने बहस किया कि यू. पी. कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (इसके बाद 'यू. पी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत प्रावधान अलग थे। राजस्थान अधिनियम में ही व्यापारियों पर दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। यू. पी. अधिनियम के तहत स्थिति अलग थी इसलिए विशिष्ट विशेषताओं पर विचार किए बिना निर्णय पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

उत्तर में उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने बहस किया कि कृषि उत्पादन के मामले (ऊपर) में निर्णय स्पष्ट रूप से लागू था। प्रावधान समान हैं और इसलिए उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय पर भरोसा करना उचित ठहराया।

प्रतिद्वंद्वी की प्रस्तुति की सराहना करने के लिए संबंधित प्रावधान दो अधिनियमों में से राजस्थान अधिनियम और उत्तर प्रदेश अधिनियम पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहाँ तक यू. पी. अधिनियम का संबंध है, धारा 17 इस प्रकार है:

" समिति की शक्तियाँ—एक समिति, इन उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम की शक्ति है -

(i) शर्तों और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन जो निर्धारित किए जाएं, या, इसलिए कारणों को दर्ज करने के बाद, ऐसा कोई भी लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण करने से इनकार कर दें।

(ii) इस अधिनियम के तहत जारी या नवीनीकृत लाइसेंसों को निलंबित या रद्द करना:

बशर्ते कि लाइसेंस रद्द करने से पहले के आधार को छोड़कर जिसमें धारा 37 के तहत सजा हो सकती है प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का समिति उसे उचित अवसर देगी।

(iii) उद्ग्रहण और संग्रह -

(क) ऐसी फीस जो लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए निर्धारित की जा सकती है; सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2004] पूरक 5 एस सी आर।

और

(ख) बाजार शुल्क जो बिक्री के लेन-देन पर देय होगा बाजार क्षेत्र में ऐसी दरों पर निर्दिष्ट कृषि उपज, एक प्रतिशत से कम और ढाई से अधिक नहीं इस प्रकार बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों की कीमत का प्रतिशत जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और विकास उपकर जो बिक्री के ऐसे लेन-देन पर आधे की दर से देय होगा। इस प्रकार बेचे गए कृषि उत्पाद की कीमत का प्रतिशत, और शुल्क या विकास उपकर निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जाएगा:

(1) यदि उपज को कमीशन एजेंट के माध्यम से बेचा जाता है, तो खरीद से उपकर और उसी का भुगतान करने के लिए समिति को उत्तरदायी होगा ;

(2) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उपज खरीदता है, तो व्यापारी बाजार शुल्क और विकास उपकर का भुगतान समिति के लिए करने के लिए उत्तरदायी होगा।;

(3) यदि उत्पाद किसी अन्य व्यापारी से किसी व्यापारी द्वारा खरीदा जाता है, तो उत्पाद बेचने वाला व्यापारी इसे खरीदार से प्राप्त कर सकता है और समिति को बाजार शुल्क और विकास उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

बशर्ते कि किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, उपज बेचने वाला व्यापारी उत्तरदायी होगा और हमेशा 12 जून, 1973 से समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी समझा जाएगा और इस आधार पर ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं होगा कि उसने खरीदार से इसका एहसास नहीं हुआ;

बशर्ते कि उपज बेचने वाला व्यापारी जमीनी स्तर पर विकास उपकर का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त नहीं होगा। कि उसे खरीदार से इसका एहसास नहीं हुआ है;

(4) ऐसी उपज की बिक्री के किसी अन्य मामले में, खरीदार समिति को बाजार शुल्क और विकास उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

राजस्थान अधिनियम और नियमों में धारा 17 और नियम 59 प्रासंगिक हैं। इस प्रकार पढ़िए:

" धारा 17-बाजार शुल्क एकत्र करने की शक्ति: बाजार समिति कृषि पर निर्धारित तरीके से लाइसेंसधारियों से शुल्क एकत्र करेगा।

उनके द्वारा बाजार क्षेत्र में लाई गई या बेची गई उपज ऐसी दर पर जो हो सके राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अधिकतम 2 रुपये प्रति सौ रुपये के मूल्य के अधीन कृषि उपज।

नियम 59-उपकर और शुल्क की वसूली: ( 1 ) कृषि पर उपकर जैसे ही इसे लाया और बेचा जाता है, उत्पाद का भुगतान किया जाएगा। बाजार क्षेत्र जैसा कि उपनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) बाजार शुल्क का भुगतान 'खरीदार' द्वारा निम्नलिखित नियमों से किया जाएगा तरीका-

(1) यदि निर्दिष्ट कृषि उपज को "ए" के माध्यम से बेचा जाता है। वर्ग दलाल "ए" वर्ग दलाल खरीदार से बाजार शुल्क लेगा। और उसी के अनुसार बाजार समिति के पास जमा करें उप-कानूनों में निर्दिष्ट प्रक्रिया।

(ii) यदि निर्दिष्ट कृषि उपज एक के माध्यम से नहीं बेची जाती है। " एक वर्ग दलाल, विक्रेता खरीदार से बाजार शुल्क लेगा। और इसे बाजार समिति के पास निर्दिष्ट तरीके से जमा करें। बाय में-कानून।

(iii) यदि विक्रेता लाइसेंसधारी नहीं है, तो बाजार शुल्क होगा - क्रेता द्वारा उपनियमों में निर्दिष्ट तरीके से जमा किया गया।

व्याख्या: 'खरीदार' शब्द का अर्थ है और इसमें एक व्यक्ति भी शामिल है। जिसने एक व्यापारी या दलाल या किसी अन्य प्रचालक के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया हो बाजार क्षेत्र में कृषि उपज की खरीद के लिए। राजस्थान अधिनियम और उत्तर प्रदेश अधिनियम के बीच एक बुनियादी अंतर है।

जहां तक बाजार शुल्क लगाने का संबंध है, अधिनियम बनाएँ। उत्तर प्रदेश अधिनियम में खरीदार पर देयता तय करने का एक विशिष्ट संदर्भ है और राजस्थान अधिनियम में देयता लाइसेंसधारी पर है।

अधिनियम की धारा 14 बाजार समिति की जारी करने की शक्ति से संबंधित है। लाइसेंस। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि बाजार समिति नियमों और उप-कानूनों के अनुसार व्यापारियों, दलालों, भारोत्तोलकों को लाइसेंस जारी और नवीनीकरण कर सकती है। मापने वाले, सर्वेक्षक, गोदाम मालिक और अन्य व्यक्ति "। धारा 17 सौदे बाजार शुल्क एकत्र करने की शक्ति के साथ। यह शुल्क बाजार क्षेत्र में लाइसेंसधारियों द्वारा लाए गए या बेचे गए कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। बाजार समिति के पास लाइसेंसधारियों से बाजार शुल्क एकत्र करने की शक्ति है। यह तथ्यात्मक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कि लाइसेंसधारी "कृषि उपज" लाया या बेचा (जैसा कि परिभाषित किया गया है)। 'बाजार क्षेत्र' में धारा 2 (1) (i) में (जैसा कि धारा 2 (1) (viii) में परिभाषित किया गया है अर्थात् कोई भी धारा 4) के तहत बाजार क्षेत्र घोषित किया गया। लाइसेंसधारक से बाजार शुल्क का संग्रह निर्धारित तरीके से होना चाहिए। धारा 2 (1) (xii) के अनुसार निर्धारित का अर्थ धारा 36 के तहत नियमों द्वारा निर्धारित है। धारा 17 को पढ़ने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि बाजार शुल्क का भुगतान करने का दायित्व लाइसेंसधारी का है और संग्रह निर्धारित तरीके से होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि कौन भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

उच्च न्यायालय द्वारा मूल भेद को नजरअंदाज कर दिया गया है। अंतर शब्दावलीगत है अर्थात् उत्तर प्रदेश अधिनियम में 'खरीदार' और राजस्थान अधिनियम में 'लाइसेंसधारी' पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।

दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक अंतर पर ध्यान नहीं दिया राजस्थान अधिनियम की धारा 17 और उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 17 के बीच। जहां तक राजस्थान के मामलों का संबंध है, उत्तर प्रदेश के मामले में लागू तर्क यानी कृषि उत्पादन के मामले (उपरोक्त) को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानूनी स्थिति अलग है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रावधानों की तुलना किए बिना कोई

कारण नहीं बताया कि उसने क्यों सोचा कि उत्तर प्रदेश का मामला वर्तमान अपीलों पर लागू था। यद्यपि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि गहन विश्लेषण किया गया है और इसलिए आगे किसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, केवल इस आधार पर कि उच्च न्यायालय यू. पी. अधिनियम और अधिनियम की भाषा में अंतर को नोटिस करने में विफल रहा, इस मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करने की आवश्यकता है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णयों को दरकिनार करते हैं और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजते हैं क्योंकि दोनों मामलों में अर्थात् 1999 की आपराधिक अपील 667 और 435/2002 की कानूनी स्थिति समान है। उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति की जांच की जानी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अपीलों की अनुमति है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

एसकेएस.

मु0 अब्दुल नसीर